# कुमाऊं की 25 बेटियों को दैनिक जागरण आज करेगा सम्मानित

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी : बेटियां संघर्ष करते हुए सफलता की उड़ान भर रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला-संस्कृति, विज्ञान, साहित्य आदि क्षेत्रों में कामयाबी की नई कहानी गढ़ते हुए प्रदेश का मान बढ़ा रही हैं। दैनिक जागरण कुमाऊं की ऐसी ही 25 बेटियों को सम्मानित करने जा रहा है। 'नाज है बेटियों पे' कार्यक्रम के तहत बेटियों का सम्मान किया जाएगा।

यह भव्य आयोजन शनिवार यानी आज शाम तीन बजे से हल्द्वानी में नैनीताल रोड स्थित होटल आईटीसी फार्च्यून में होगा, जिसमें जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल आयोजन के मुख्य अतिथि होंगे, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरम्वाल विशिष्ट अतिथि होंगी, जिनके हाथों से पुरस्कार के लिए चयनित बेटियों को सम्मानित किया जाएगा।

Jagran

नाज है बेटियों पे
एक सलाम बेटियों की कामयाबी के नाम

### इन्हें किया जाएगा सम्मानित

**कला एवं संस्कृति:** भव्या पाटनी, मंजू आर साह, दिव्यांशी मिश्रा, ऋषिका, रश्मि भट्ट, अंजली, नियति अवस्थी, अहाना सचदेवा, सुप्रिया बिष्ट, अनुष्का भट्ट, अभिलाषा जोशी, दिव्या भट्ट, हर्षिता आर्या।

**खेल :** रिया खरायत, हर्षिका रिखाड़ी, श्रीपर्णा जोशी, साक्षी बिष्ट, पूनम दूबे, सर्वजीत कौर, अदिति सिंह, समाक्षी सिंह, मुद्रा प्रवेश।

**शिक्षा :** अपूर्वा भट्ट, रिद्धिमा बौरा, सारा जोशी।

# शहर में बहेगी विकास की बयार

## हल्द्वानी में हाई कोर्ट आने से आम लोगों को मिलेगा न्यायिक लाभ

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: अब हल्द्वानी राज्य की न्यायिक राजधानी के तौर पर पहचानी जाएगी। बेलबाबा मंदिर के सामने हाई कोर्ट शिफ्टिंग को लेकर कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। यहां पर हाई कोर्ट शिफ्ट होने से हल्द्वानी में विकास की नई बयार बहेगी। मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी और आम लोगों को न्यायिक सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी।

हल्द्वानी में हाई कोर्ट शिफ्ट होने के बाद यहां लोगों का आवागमन स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी। ऐसे में शहर के आधारभूत विकास में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। परिवहन सुविधा को मजबूत किया जाएगा। बिजली, पानी, सीवर से जुड़ी सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा। फ्लाईओवर, बाईपास, नई सड़कें बनाई जाएंगी।

मुख्य शहर से बेलबाबा मंदिर लगभग 10 किमी दूर है। ऐसे में शहर के आउटर सर्कल में स्थित बेलबाबा मंदिर क्षेत्र के आसपास के गांवों में भी सुविधाएं बढ़ेंगी।



हाई कोर्ट के हल्द्वानी के रामपुर रोड में बनने की जानकारी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से मिली है। इस संबंध में शासन स्तर से जो भी दिशा-निर्देश मिलेंगे उनका तत्परता से पालन किया जाएगा। -ललित मोहन रयाल, डीएम

### नैनीताल का बोझ होगा कम लोगों के लिए भी आसानी

पर्यटन केंद्र और हाई कोर्ट दोनों एक साथ होने से नैनीताल में अत्यधिक भीड़, ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या रहती है। हाई कोर्ट हल्द्वानी आने से हाई कोर्ट के काम से जाने वाले लोगों को नैनीताल नहीं जाना पड़ेगा। इससे आम लोगों को भी राहत मिलेगी। साथ ही उन्हें नैनीताल के जाम में से नहीं जूझना पड़ेगा और पहले से बोझ के तले दबे नैनीताल के लिए यह पर्यावरण की दृष्टि से संजीवनी की तरह होगा।

### शहर की कानून-व्यवस्था सुधरेगी

शहर में हाई कोर्ट आने से सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार होगा। हर गतिविधि पर जजों की सीधी नजर होगी जिससे पुलिस पहले से अधिक चौकन्नी रहेगी। वहीं हाई कोर्ट शिफ्टिंग से शहर में वकीलों और कानून के जानकार बढ़ेंगे। ऐसे में ला कालेजों, ला रिसर्च सेंटर्स और लाइब्रेरी बनने की संभावना बढ़ेगी। इससे स्थानीय युवाओं को भी काफी लाभ मिलेगा।

क्षेत्र में व्यवसायीकरण भी बढ़ेगा, जिससे अप्रत्यक्ष रोजगार में बढ़ावा होगा। इसके साथ ही हाई कोर्ट बनने के बाद कानून और न्याय व्यवस्था से जुड़े पेशेवरों (जैसे वकील, नोटरी, टाइपिस्ट, मुंशी, अनुवादक, पैरा-लीगल स्टाफ) के लिए नए अवसर बनेंगे।

### जमीन के दाम में होगा इजाफा

जिस तरह गौलापार में हाई कोर्ट शिफ्टिंग की खबरों से जमीन के दाम आसमान छू रहे थे, वहीं अब रामपुर रोड से सटे गांवों और आसपास के क्षेत्रों में भी जमीन के दाम तेजी से उछाल मारेंगे। हाई कोर्ट से जुड़े तमाम लोग नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होंगे, ऐसे में गन्ना सेंटर, पंचायतघर क्षेत्र, फूलचौड़, जीतपुर नेगी, बजवालपुर, हरिपुर जमन सिंह, किशनपुर घुड़दौड़ा समेत अन्य क्षेत्रों में जमीन के दाम बढ़ेंगे।

### शिफ्टिंग का किया स्वागत

अधिवक्ताओं ने बेलबाबा मंदिर क्षेत्र में हाई कोर्ट की शिफ्टिंग का स्वागत किया है। अधिवक्ता ललित जोशी ने कहा कि सरकार ने यह जनहित में निर्णय लिया है। सरकार का उद्देश्य न्याय सुलभ कराना है। यह फैसला हल्द्वानी के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।



ललित • स्वयं

# आरोपितों को रिमांड पर देने से इन्कार करने का आदेश रद

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल के एक हाई-प्रोफाइल मामले के आरोपितों गौरव कुल्याल (उर्फ गोली), राहुल सिंह रावत, गौरंग रौतेला (उर्फ गोलू) और अजय कुल्याल को रिमांड पर देने से इन्कार करने से संबंधित आदेश को रद कर दिया है। कोर्ट ने मामले को वापस भेजते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल को इस मामले को दोबारा विचार करने के लिए किसी दूसरी अदालत को सौंपने के आदेश पारित किया है।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने कहा कि बीएनएस की धारा-109 के तहत रिमांड देने से इन्कार करने का मजिस्ट्रेट का निर्णय बिना सोचे-समझे लिया गया था। अदालत ने खास तौर पर उस तरीके पर सवाल उठाए, जिससे पीड़ित रमेश किरौला (जो अभी भी कोमा में हैं) को लगी गंभीर चोटों की रिपोर्ट को देखा गया था। एकलपीठ में शिकायतकर्ता हिमांशु रैक्वाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। हिमांशु ने एसीजेएम नैनीताल की कोर्ट के 20 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी।

### घायलों में से एक अभी भर्ती

एकलपीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष की अर्जी पर रिमांड से इन्कार करने का आदेश बिना सोचे-समझे दिया गया था, क्योंकि घायलों में से एक रमेश किरौला अभी भी दिल्ली के मैक्स अस्पताल के आइसीयू में हैं और बयान देने की हालत में नहीं हैं। तस्वीरें भी दिखाई गई हैं और ताजा जानकारी के अनुसार वह कोमा में हैं। मजिस्ट्रेट के आदेश की समीक्षा करने पर हाई कोर्ट ने पाया कि मेडिकल रिपोर्ट पर ठीक से विचार न करने के कारण अहम सबूतों को नजरअंदाज कर दिया गया था। मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि किरौला को जानलेवा चोटें आई थीं, वह कोमा में थे, जिससे वह बयान देने में असमर्थ थे। अदालत ने कहा कि प्रक्रिया में हुई इन खामियों से मजिस्ट्रेट के आदेश पर संदेह पैदा होता है, खासकर इस गलत उम्मीद को लेकर कि किरौला अपनी हालत के बावजूद गवाही दे पाएंगे।

जिसमें अभियोजन पक्ष की आरोपियों की रिमांड की मांग को खारिज कर दिया था, जबकि मामले में गंभीर परिस्थितियां शामिल थीं किरौला की हालत नाजुक थी।

# जहां मिली जमीन, वहां से उजाड़े जाएंगे 15 हजार पौधे

ललित मोहन बेलवाल • जागरण

हल्द्वानी: आखिरकार हाई कोर्ट नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होने का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को कैबिनेट ने बेलबाबा में 30 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरण के लिए मंजूरी दी, लेकिन जिस प्लाट नंबर 46 और 47 की 73 हेक्टेयर जमीन में से स्वीकृत जमीन फाइनल करनी है, वहां से लगभग 15 हजार पौधे उजाड़े जाएंगे।

मानसून सीजन शुरू होने के बाद बेलबाबा मंदिर के सामने की खाली वनभूमि पर नया पौधरोपण किया गया। इसी क्रम में जिस प्लाट नंबर 46 और 47 का हाई कोर्ट के लिए निरीक्षण किया गया था, वहां पर भी पौधे लगाए गए।



हाई कोर्ट शिफ्टिंग के लिए भाखड़ा रेंज के प्लाट 46 और 47 से चिह्नित की जाएगी 30 हेक्टेयर जमीन

### हस्तांतरण प्रक्रिया पर बोलने से बच रहे अधिकारी

आमतौर पर अगर वन भूमि 2.25 हेक्टेयर से अधिक हो तो उसके हस्तांतरण के लिए केंद्रीय वन मंत्रालय से स्वीकृति लेनी होती है। वनभूमि की हस्तांतरण प्रक्रिया रेंज स्तर से शुरू होगी। इसके बाद आवेदन डिवीजन, सर्किल कार्यालय और मुख्यालय तक पहुंचेगा। फिर नोडल स्टेट से केंद्रीय वन मंत्रालय से आवेदन को अंतिम स्वीकृति मिलती है। लेकिन, मामला कोर्ट से जुड़ा होने के कारण वन विभाग के अधिकारी हस्तांतरण प्रक्रिया को लेकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उनका कहना है कि उच्च स्तर से जो भी आदेश मिलेंगे, उसके अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक यहां पर प्रति हेक्टेयर बीज बोने के बाद लगभग 500 पौधे लगाए गए। अब चूंकि यहीं से 30 हेक्टेयर भूमि चयनित करनी है। ऐसे में यहां पर लगे 15 हजार पौधों को हटाना पड़ेगा। यहां पर शीशम, खैर, जामुन, नीम, बेल समेत अन्य प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, प्रति हेक्टेयर 500 पौधे लगाने में लगभग दो से ढाई लाख रुपये लगते हैं। इसमें जुताई, तार और खंभे लगाने, मेड़ बनाने, बीज बोने, पौधों की खरीद और मजदूरी का खर्च शामिल होता है। यानी 30 हेक्टेयर भूमि में पौधे लगाने में 60 से 50 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

विस्तृत खबरों के लिए देखें https://www.jagran.com/local/uttarakhand_nainital-news-hindi.html

## सार-संक्षेप

### यूपीसीएल में सहायक अभियंताओं की पदोन्नति पर लगी रोक

नैनीताल : हाई कोर्ट ने उत्तराखंड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड में सहायक अभियंताओं के अधिशासी अभियंता पद पर होने वाली पदोन्नति पर रोक लगा दी है। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने यह आदेश यूपीसीएल में कार्यरत पांच सहायक अभियंताओं मनोज कुमार, वेद प्रकाश, सौरभ चमोली, नरेंद्र सिंह नेगी और गुरदीप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ताओं का पक्ष है कि वह वर्ष 2002 से कनिष्ठ अभियंता के रूप में कार्यरत थे, लेकिन प्रशासनिक चूक और एसीआर उपलब्ध न होने के कारण उनके कनिष्ठ सहयोगियों को पहले पदोन्नति दे दी गई। हालांकि बाद में 2012 की संशोधित वरिष्ठता सूची में उनका स्थान सही कर दिया गया था, जिससे वे वर्ष 2008-09 से पदोन्नति पाने के हकदार बन गए थे। (जासं)

### बेरीनाग के पूर्व सैनिक की मौत की जांच करेगी सीबीसीआइडी

नैनीताल : हाई कोर्ट ने पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग निवासी भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक दीपक सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में बड़ा आदेश पारित किया है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता हरीश मेहरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हल्द्वानी थाने में दर्ज प्राथमिकी पर जांच को तत्काल प्रभाव से सीबीसीआइडी को स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया है। कोर्ट ने जांच अधिकारी से असंतुष्ट होने पर राज्य सरकार व अपर शासकीय अधिवक्ता के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया, ताकि मामले में निष्पक्ष एवं प्रभावी जांच सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस मामले की जांच सीबीसीआईडी के कम से कम क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी की ओर से की जाएगी। (जासं)

### अधिवक्ता व साथियों के साथ मारपीट पर हाई कोर्ट सख्त

नैनीताल : हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद मल्लीताल में एक पक्ष की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद मतलूब व उनके भाई के साथ की गई मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में सुरक्षा को लेकर दायर याचिका की सुनवाई की। कोर्ट ने नैनीताल पुलिस को आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई करने, विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने व याची को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान विवेचक व मल्लीताल कोतवाली के एसएसआइ दिनेश जोशी भी कोर्ट में मौजूद रहे। शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ में अधिवक्ता मोहम्मद मतलूब की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया है कि पांच अगस्त की शाम मल्लीताल की जामा मस्जिद परिसर में दूसरे पक्ष के लोगों ने वहां पहुंचकर मारपीट शुरू कर दी। (जासं)

### अवमानना के दोषी मुख्य अभियंता को दी चेतावनी

नैनीताल : हाई कोर्ट ने उत्तराखंड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य अभियंता संजय कुमार पाठक के खिलाफ अवमानना मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। कोर्ट ने जानबूझकर आदेश की अवहेलना का दोषी मानते हुए अपने पूर्व आदेश की पुष्टि की। हालांकि बाद में आदेश का पालन होने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल होने के कारण अदालत ने कोई सजा या जुर्माना नहीं लगाया। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। राम कृष्ण ने अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि 26 फरवरी को पारित कोर्ट के आदेश के बावजूद उसके तकनीकी रूप से स्वीकृत टेंडर की वित्तीय बोली नहीं खोली गई। (जासं)

### पालिका के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में कटौती पर रोक

नैनीताल : हाई कोर्ट ने मसूरी नगर पालिका में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में कटौती पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने नगर पालिका को आदेश दिया है कि अंतिम निर्णय होने तक कर्मचारियों को वही वेतन दिया जाए, जो उन्हें आठ जून 2026 के आदेश से पहले मिल रहा था। यह अंतरिम आदेश देवेंद्र प्रसाद एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया गया। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने बताया कि पालिका के ईओ ने न्यूनतम वेतन देने की मांग को खारिज कर दिया था। (जासं)

### सचिव स्वास्थ्य को हाई कोर्ट में पेश करना होगा शपथपत्र

नैनीताल : हाई कोर्ट ने उपनल कर्मचारियों की ओर से दायर विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में उपनल कर्मी दीपक कुमार, मंजुल मेहता सहित 10 लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया है उपनल कर्मियों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नई नियुक्तियां कर रही है। (जासं)

# राज्य गठन के 26 साल बाद नैनीताल से सबसे बड़े संस्थान की होगी विदाई

किशोर जोशी • जागरण

नैनीताल : ब्रिटिशकाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी नैनीताल से अब प्रदेश के सबसे बड़े न्यायिक संस्थान हाई कोर्ट को भी अब हल्द्वानी में शिफ्ट करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रदेश की कैबिनेट ने भाखड़ा रेंज के लामाचौड़ ब्लाक क्षेत्र में वन भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने भी उत्तराखंड बार एसोसिएशन की विशेष अनुमति याचिका को निस्तारित करते हुए प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट शिफ्ट करने के लिए जहां है, जैसी है, के आधार पर भूमि हस्तांतरण के आदेश पारित किए थे। हाई कोर्ट के हल्द्वानी शिफ्ट होने के बाद शहर को प्रदेश की न्यायिक राजधानी का तमगा भी हट जाएगा। सरकार के निर्णय के बाद सवाल हर किसी की जुबां पर है कि कोर्ट रूम्स, प्रशासनिक भवनों, न्यायाधीशों के आवासों, अधिवक्ता चैंबर्स सहित अन्य अरबों खर्च कर जुटाई ढांचागत सुविधाओं का उपयोग कौन करेगा।

### आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ ने दी है हाई कोर्ट में चुनौती

हाई कोर्ट को शिफ्ट करने के सरकार व हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ के निर्णय को राज्य आंदोलनकारी अधिवक्ता संघ की ओर से चुनौती दी गई है, जिसमें हाई कोर्ट को भी पक्षकार बनाया है। याचिका में प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम व भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन बताया। याचिकाकर्ता रमन कुमार शाह का कहना है कि प्रस्तावित वन भूमि आरक्षित होने के साथ ही हाली गलियारा भी है।



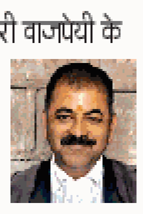
हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने का राज्य कैबिनेट का निर्णय स्वागतयोग्य है। हल्द्वानी में एक ही छत के नीचे जजों, वादकारियों व अधिवक्ताओं को सुविधाएं मिलेंगी। -**डीसीएस रावत अध्यक्ष हाई कोर्ट बार एसोसिएशन।**



हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट किया जाना उचित निर्णय है। इससे वादकारियों को सुविधा मिलने के साथ ही पर्यटन नगरी में दबाव कम होगा। हल्द्वानी में कोर्ट शिफ्ट होगी तो सुविधाएं बढ़ेंगी। -सौरव अधिकारी महासचिव हाई कोर्ट बार एसोसिएशन।



नैनीताल में हाई कोर्ट होने से न्यायाधीशों की सुविधाओं में कभी कटौती नहीं हुई। सरकार को जरूरी लगता है तो मजखाली में हाई कोर्ट शिफ्ट कर दे। -**अवतार सिंह रावत, वरिष्ठ अधिवक्ता हाई कोर्ट**



एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व की सरकार ने पहाड़ का स्थायी संस्थान बनाया था, जिसे अब उनकी ही पार्टी ने शिफ्ट करने का निर्णय कर पहाड़ विरोधी चेहरा उजागर किया है। -भुवनेश जोशी, अधिवक्ता हाई कोर्ट



रिजर्व फारेस्ट की जमीन के ट्रांसफर के तहत हाई कोर्ट को कहीं और ले जाने की अनुमति तब तक नहीं है, जब तक कि केंद्र सरकार उस आरक्षित वन भूमि का रिजर्व का दर्जा खत्म न कर दे। -डा. कार्तिकेय हरिगुप्ता, अधिवक्ता हाई कोर्ट।






# दो बार समय देने के बाद भी शपथपत्र दायर नहीं करने पर हाई कोर्ट नाराज

जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने प्रदेश के सरकारी बीएड कालेजों व विवि से मान्यता प्राप्त कालेजों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने दो बार पहले भी समय देने के बाद भी जवाबी शपथपत्र दाखिल नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने सरकार को अतिरिक्त समय देते हुए दो सप्ताह में अपना शपथपत्र देने को कहा है। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में पिथौरागढ़ निवासी डा. राजेश पाण्डे की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि दो वर्ष बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में कोई शपथपत्र पेश नहीं किया है।

ऊपर से सरकार हर साल मान्यता प्राप्त कालेजों की संबद्धता बढ़ा रही है जबकि कालेजों में ना तो शिक्षक हैं, ना ही छात्रों के लिए कोई सुविधाएं उपलब्ध हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि छात्र-छात्राओं से पूरा शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई बीएड कालेजों में आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी दिशा निर्देशों का अवलोकन कोर्ट को कराया, सुप्रीम कोर्ट ने अस्पष्ट किया था कि उचित प्रशिक्षण और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के बिना तैयार हुए शिक्षक प्रभावी शिक्षण कार्य नहीं कर सकते और इससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

### यौन शोषण मामले में भवाली के व्यापारी नेता को राहत नहीं

नैनीताल : हाई कोर्ट ने किशोरी का यौन शोषण करने और उसे डराने-धमकाने के आरोपित भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे की जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पांडे को फिलहाल कोई राहत देने से इन्कार करते हुए राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी और उसकी उम्र 17 वर्ष थी। अदालत ने कड़ी मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे कृत्य क्यों कर रहे हैं, जो कभी समाज का आईना हुआ करते थे। कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जैसे ही ऐसे लोगों के पास पैसा आता है, यह भूल जाते हैं कि उनकी इन हरकतों और आपराधिक कृत्यों का उनके अपने परिवार और बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल पीड़िता ने भवाली उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेश पांडे के विरुद्ध शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मल्लीताल कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।


बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
शाखा : क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, प्रथम तल क्षेत्रीय कार्यालय, रुद्रपुर, गाबा चौक के पास, काशीपुर रोड, रुद्रपुर- 263153
ई-नीलामी सूचना

चल/अचल संपत्तियों की नीलामी सूचना "परिशिष्ट IV-A" नियम 6(2) एवं 9(1) देखें

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के सुरक्षा अधिनियम (पवर्तन) 2002 के साथ पठित नियम 6(2) एवं 9(1) के अधीन बैंक को बंधक रखी चल/अचल संपत्तियों की ई-नीलामी

सर्वसाधारण को साधारणतया एवं ऋणी एवं जमानतदार को विशेषतया यह सूचना दी जाती है कि निम्न वर्णित संपत्ति बैंक ऑफ बड़ौदा के पास बंधक है एवं जिसका कब्जा बैंक के संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया है एवं बैंक की बकाया राशि मय ब्याज, खर्चे एवं कीमत इत्यादि सहित वसूलने हेतु निम्न शर्तों एवं नियमों के अंतर्गत ई-नीलामी द्वारा विक्रय की जा रही है। निम्न वर्णित संपत्तियां "जहां है जैसी है एवं जो है जैसी है" के आधार पर ई-नीलामी के द्वारा विक्रय की जायेगी। बकाएदार/जमानतदार/सम्पत्ति/यों का विवरण/बकाया धनराशि/रिर्जव प्राईज/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, आरक्षित मूल्य एवं न्यूनतम बोली की वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है :-

| क्र. सं. | ऋणी/गारन्टर का नाम व पता | चल/अचल सम्पत्ति का विवरण | रिजर्व प्राईज / ईएमडी / न्यूनतम बोली की वृद्धि राशि | दिनांक एवं ई-नीलामी के प्रारम्भ का समय / कब्जे का प्रकार | मांग सूचना की तिथि / कब्जे की तिथि / बकाया धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. **मैसर्स सम्राट एंटरप्राइजेज, द्वारा इसके प्रोपराइटर श्रीमती मोनिका अग्रवाल पत्नी श्री संजीव अग्रवाल,** प्लॉट नं. 8/1, हिमालयन फूड पार्क, महुआखेड़ा, काशीपुर, जिला- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713 2. श्रीमती मोनिका अग्रवाल पत्नी श्री संजीव अग्रवाल (प्रोपराइटर मैसर्स सम्राट एंटरप्राइजेज), पता- प्लॉट नं. | बंधक अचल सम्पत्ति (भूमि व भवन) के सभी भाग व हिस्से जो कि खसरा सं. 304, 305, प्लॉट सं. 8/1 महुआखेड़ा गंज, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर में स्थित है। क्षेत्रफल 21520 वर्ग फुट या 2000 वर्ग मीटर। सम्पत्ति श्रीमती मोनिका अग्रवाल पत्नी श्री संजीव अग्रवाल के नाम पर विधिवत पंजीकृत है (लीज डीड सीरियल सं. 6348, दिनांक 01.09.2017 को हिमालयन फूड पार्क द्वारा श्रीमती मोनिका अग्रवाल पत्नी श्री संजीव अग्रवाल के पक्ष में जारी की गई है)। सीमायें (लीज डीड के अनुसार)-पूरब में दूसरों के प्लॉट, पश्चिम में दूसरों के प्लॉट, उत्तर में 15 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण में चक रोड। | ₹ 1,98,00,000.00 / ईएमडी ₹ 19,80,000.00 / न्यूनतम बोली की वृद्धि राशि ₹ 25,000.00 | 25.08.2026 अपरान्ह 12:00 से सायं 05:00 / कब्जे का प्रकार: भौतिक कब्जा | 05.01.2024 / 20.05.2024 / ₹ 3,59,39,936.00 (रुपये तीन करोड़ उनसठ लाख उनतालीस हजार नौ सौ छत्तीस मात्र) + ₹ 14,73,943.15 (रुपये चौदह लाख तिहत्तर हजार नौ सौ तिरालिस एवं पैसे पंद्रह मात्र) (अप्राप्त ब्याज) + अप्रयुक्त ब्याज + कानूनी शुल्क + अन्य शुल्क एवं ब्याज 26.12.2023 से प्रभावी |

नियम एवं शर्तों के लिए कृपया इस क्यू आर को स्कैन करें

8/1, हिमालयन फूड पार्क, महुआखेड़ा, काशीपुर, जिला- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713 3. श्रीमती राजबाला अग्रवाल पत्नी श्री राकेश अग्रवाल (जमानती), पता- वार्ड नं. 11, मोहल्ला ओझान, काशीपुर, जिला- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713 4. श्री सौरभ अग्रवाल पुत्र श्री राकेश कुमार अग्रवाल (जमानती), पता- वार्ड नं. 11, मोहल्ला ओझान, काशीपुर, जिला- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713 5. श्रीमती दिशा अग्रवाल पत्नी श्री गौरव अग्रवाल (जमानती), पता- वार्ड नं. 11, मोहल्ला ओझान, काशीपुर, जिला- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713 6. श्रीमती दीप्ति अग्रवाल पत्नी श्री सौरभ अग्रवाल (जमानती), पता- वार्ड नं. 11, मोहल्ला ओझान, काशीपुर, जिला- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713 7. श्री संजीव अग्रवाल पुत्र एमआर शंकर लाल (जमानती) पता- हाउस नं. 24 बी/2, आदर्श कॉलोनी, सिविल लाइन्स, रामपुर, उत्तर प्रदेश-244901 8. श्री मोहम्मद अली पुत्र श्री मोहब्बे अली (जमानती), पता-मोहल्ला अल्लीखां, वार्ड नंबर 10, काशीपुर, जिला- ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड- 244713

विक्रय के निबन्धन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया हमारी वेबसाईट https://www.bankofbaroda.in/e-auction.html एवं https://baanknet.com देखें। भावी बोली दाता प्राधिकृत अधिकारी, मो0-8477000519, 8477009621 से भी सम्पर्क कर सकते हैं। नोट : किसी भी त्रुटि या विवाद की स्थिति में इस नीलामी नोटिस का अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया दिनांक 08.08.2026 को प्रकाशित नोटिस मान्य होगा।

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि व समय : 18.08.2026 को अपरान्ह 12 बजे से सायं 05:00 बजे तक

सरफासी ऐक्ट, 2002 के तहत बिक्री हेतु 15 दिन का कानूनी नोटिस

एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटरों को अधिसूचित किया जाता है कि वे उपरिवर्णित राशि का भुगतान अद्यतन ब्याज और अनुषंगी खर्चों सहित नीलामी की तिथि से पहले कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई, की वसूली ब्याज एवं लागत सहित की जाएगी।

दिनांक : 07.08.2026 स्थान : बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखा, रुद्रपुर प्राधिकृत अधिकारी



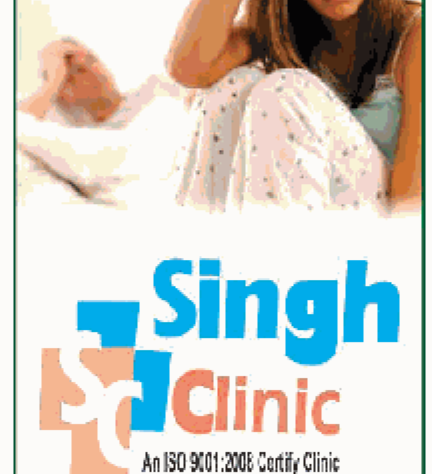
समस्या आपकी समाधान
INTERNATIONAL SEXOLOGIST

यदि आप भी धात, स्वप्नदोष, ल्यूकोरिया, मर्दाना कमजोरी, गुप्त रोगों एवं शुक्राणुओं की कमी का राजवैद्यों के नुस्खों पर आधारित कीमती एवं बहुमूल्य रत्नों, भस्मों द्वारा सबसे उचित आयुर्वेदिक इलाज करवाना चाहते हैं तो मिलें

**मनोज कुमार –** मेरी शादी को 4 वर्ष हो चुके थे। मैं शीघ्रपतन रोग से पीड़ित था कम्प्यूटर इंजीनियर होने के साथ साथ जॉब में अपने पार्टनर से मिलता था तब मुझे 30 से 40 सेकेण्ड में मेरा शीघ्रपतन हो जाता था। एक दिन हम दोनों ने फैसला लिया और सीधे सिंह क्लीनिक पहुँचे दोनों से इसका इलाज करवाया। डॉ. सिंह ने जैसे मुझे दवाई दी मैं एक सप्ताह में ठीक हो गया। मुझमें वही जोश आने लगा जो जोश जवानी में आता था। आज मेरा वैवाहिक जीवन सफल हुआ। आज मैं जो कुछ हूँ वो डॉ. सिंह की वजह से हूँ।

**अभिषेक –** मेरी बचपन की गलतियों से मुझे प्रमेह रोग हो गया। मेरी याददाश्त कमजोर हो गयी। धात एवं स्वप्नदोष रोग से ग्रसित होकर निराश हो चुका था। मैं विभिन्न दवाखानों में इलाज कराकर थक चुका था। फिर मुझे सिंह क्लीनिक के बारे में रेडियो एफ.एम. के द्वारा पता चला और सिंह क्लीनिक पर इलाज हेतु पहुंचा। डॉ. साहब को तुरन्त बताया और उनके मार्गदर्शन से इलाज कराकर मैं ठीक हो गया। डॉ. सिंह का बहुत-बहुत धन्यवाद!

WORRIED ABOUT YOUR SEXUAL HEALTH?



Singh Clinic
An ISO 9001:2008 Certify Clinic



DR. V.P. SINGH
D.Lit. (Ayurveda)
स्त्री एवं पुरुष गुप्त रोग विशेषज्ञ
पता :- रॉयल कॉलोनी, पीलीभीत बाईपास रोड, सैटेलाइट बस स्टैण्ड से 1 किलोमीटर आगे, सतीपुर चौराहा, बरेली।
9837057107
9837343729
Website : sexologistvpsingh.com
Website : drvpsinghsexologist.com